NAVODYA TIMES, Delhi, 19.7.2017
Page No. 11, Size:(21.18)cms X (21.63)cms.

बिछड़ों को मिलाएगा, क्रिमिनल्स को पकड़वाएगा 'आधार कार्ड'

आधार हमारी पहचान

उत्तर भारत में आधार कार्ड बनवाने में हिमाचल सबसे आगे, पंजाब भी साथ-साथ और हरियाणा भी तेजी से बढ़ रहा मंजिल की तरफ

हरिश्चंद्र

चंडीगढ़, 18 जुलाई : केंद्र सरकार का विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) देशभर में अनाथालयों में भी सभी का आधार कार्ड बनाने पर काम कर रहा है। इसके अलावा भिखारियों का भी आधार कार्ड बनाने की योजना बनाई जा रही है। इससे जहां देश भर में सभी का आधार कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा होगा, वहीं ऐसे बच्चों व लोगों की भी पहचान मुमकिन हो सकेगी जो विभिन्न कारणों से अपने परिवार से बिछड़ गए हों। सभी लोगों के आधार कार्ड बनने से वे क्रिमिनल भी पकड़ में आ सकते हैं जो अपना हुलिया बदलकर काफी समय से पुलिस को चकमा दे रहे हैं। हालांकि आधार से जुड़े अधिकारी इस बारे में यह कहकर कुछ बताने से इंकार कर रहे हैं कि केवल दिल्ली मुख्यालय को ही इस बारे कोई सूचना देने का अधिकार है, मगर सूत्रों के मुताबिक इन दोनों योजनाओं को जल्द ही अमल में लाया जाएगा। यू.आई.डी.ए.आई. के सूत्रों के मुताबिक अनाथालयों में आधार बनाने पर यदि किसी की उंगलियों की छाप लेते समय आवेदन रद्द हो जाता है तो साफ है कि उस बच्चे का देश में कहीं न कहीं आधार कार्ड बना है। ऐसे में उसकी उंगलियों की पहचान के जरिए उसका पूर्व का पता लग जाएगा और उक्त बच्चा अपने परिवार से दोबारा मिल सकेगा।

हाल ही में कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं जब आधार के जरिए बच्चे वापस अपने परिवार से मिल पाए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कई बार बच्चों का अपहरण कर या उन्हें बरगला कर दूसरे राज्यों में बेच दिया जाता है। इस मानव तस्करी से कई बच्चे भिखारियों के गैंग के हत्थे चढ़ जाते हैं।

सभी भिखारियों का यदि आधार बनाया गया तो जबरन भीख मांगने के धंधे में धकेले गए बच्चे वापस अपने परिवार को मिल सकेंगे, बशर्ते उसका पहले आधार बना हो।

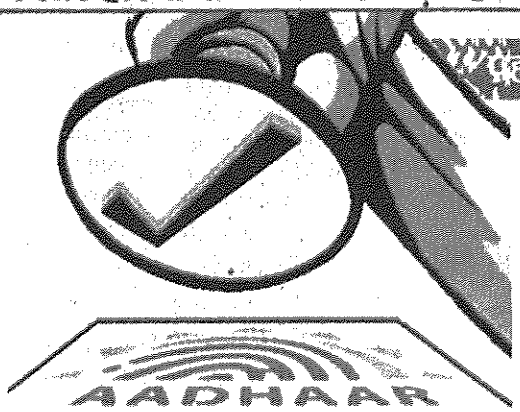

पहचान आसान

अनाथालयों में आधार बनाने पर यदि किसी की उंगलियों की छाप लेते समय आवेदन रद्द हो जाता है तो साफ है कि उसका देश में कहीं न कहीं आधार कार्ड बना हुआ है।

मृतक का आधार कार्ड नहीं होता रद्द

आधार से जुड़ी एक अहम जानकारी यह भी है कि किसी भी मृत व्यक्ति का आधार कार्ड रद्द नहीं किया जाता, यानी उसका रिकार्ड डाटा बैंक में ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी गलत वजह से खुद को मृतक साबित करके यदि किसी तरह का कोई फायदा उठाया जाता है या पुलिस रिकार्ड में खुद को मृतक साबित करने का प्रयास किया जाता है और बाद में यदि वह अपना आधार कार्ड बनवाने की कोशिश करता है तो पुराने रिकार्ड में दर्ज उंगलियों आदि के निशान के कारण वह तुरंत पकड़ में आ सकता है।

हिमाचल आगे

99.9% के बने आधार

उत्तर भारत में आधार कार्ड बनवाने में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। यहां 99.9 फीसदी तक लोग आधार कार्ड बनवा चुके हैं।

पंजाब भी साथ-साथ, 99.9 फीसदी के बने आधार

पंजाब भी तीन करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है और 17 जुलाई तक लगभग 99.9 प्रतिशत पहुंच गया है। 0-5 आयु वर्ग का जिक्र करें तो पंजाब इस मामले में बहुत पीछे है, जहां यह आंकड़ा 50 प्रतिशत को भी नहीं छू पाया।

हरियाणा पीछे, 98.8 फीसदी के बने आधार

दूसरी ओर हरियाणा इस मामले में थोड़ा पीछे है, जहां 98.8 लोग आधार कार्ड बनवा चुके हैं। वहीं यदि 0-5 आयु वर्ग का जिक्र करें तो हरियाणा सबसे आगे है। वहां इस आयु वर्ग के बच्चों के करीब 70 प्रतिशत आधार बन चुके हैं।

आधार बनाने में जम्मू-कश्मीर फिसड्डी

उत्तर भारत में केवल जम्मू-कश्मीर में अब तक मात्र 68 प्रतिशत ही आधार कार्ड बन पाए हैं। वहीं 0-5 आयु वर्ग में एक फीसदी बच्चों के आधार कार्ड ही अब तक बन पाए हैं। आधार से जुड़े आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि जम्मू-कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के दस जिलों में से जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, ऊधमपुर, रियासी, किश्तवाड़ व डोडा में आधार कार्ड बनवाने के प्रति लोगों ने ज्यादा रुचि दिखाई है जबकि घाटी के श्रीनगर, बड़गाम, कुपवाड़ा, बारामुला आदि जिलों में लोगों का उत्साह कम रहा है। खास बात यह है कि लद्दाख क्षेत्र के कारगिल जिले में 1.43 लाख की आबादी में से एक लाख और लेह जिले की करीब डेढ़ लाख की आबादी में से करीब 89,000 लोग अपना आधार कार्ड बनवा चुके हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने हालांकि इस बारे में तर्क दिया कि कश्मीर में हालात के कारण थोड़ा कम आधार कार्ड बन पाए हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि आधार बनाने के लिए टीम को स्थानीय जिला प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि संबंधित जिले में किसी वजह से बिगड़े हालात में जिला प्रशासन आधार कार्ड बनाने का काम रोकने को कहता है तो तुरंत काम रोक दिया जाता है, जबकि बाकी राज्यों में ऐसे नियम नहीं हैं। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण भी आधार बनाने को लेकर ज्यादा सक्रियता बरती जाती है ताकि कोई गलत व्यक्ति अपना आधार कार्ड न बनवा पाए।

घपले करने वाली एजेंसियों के लाइसेंस कैंसिल

आधार कार्ड बनाने में निचले स्तर पर कुछ एजेंसियों द्वारा किए घपले को देखते हुए सरकार ने आधार बनाने का समूचा कार्य जल्द सरकारी भवनों में शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। 31 अगस्त के बाद आधार कार्ड केवल सरकारी भवनों या सरकार के नियंत्रण वाले भवनों में ही बन सकेंगे। गौरतलब है कि पंजाब में कुछ जगह पर आधार बनाने के लिए नियुक्त एजेंसियों द्वारा पैसे लेकर आधार बनाने की शिकायतें सामने आई थीं जिसके बाद इनके लाइसैंस कैंसिल कर दिए गए हैं। मगर इससे आधार बनाने के इच्छुक लोगों को मुश्किल आने लगी थी। यही वजह है कि सरकारी भवनों में ही अब आधार बनाने का फैसला लिया गया है।